राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में – एक अध्ययन

आदित्य सिन्हा*
पारस रत्न**

प्रस्तुत लेख बिहार में केंद्र द्वारा पोषित योजना – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्तमान स्थिति के बारे में एक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। बिहार राज्य में जो कि शिक्षा के समस्त सूचकांकों में पिछड़ा हुआ है, इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास किस प्रकार क्रियान्वित हो रहे हैं, देखने का एक प्रयास है।

प्रस्तावना

प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता रोमिला थापर ने रेखांकित किया है कि 'हिंदुस्तान का स्वर्णिम इतिहास, बिहार राज्य का इतिहास है।' जो राज्य कभी चन्द्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक के शासन का केंद्र बिंदु रहा हो, वह राज्य जिसने दुनिया को बौद्ध व जैन धर्मों से अवगत करवाया वह राज्य जिसकी उर्वरा भूमि में सबसे पहले लोकतंत्र के बीज बोए गए, वह राज्य जिसने विश्व को नालंदा व विक्रमशिला जैसे आदि व अग्रगामी विश्वविद्यालय प्रदान किए, वह राज्य जिसकी धरा पर विदेशी विद्वान अध्ययन के लिए लगातार आते रहे... शायद इसलिए ही अलबशम ने अपनी पुस्तक ''वंडर देट वाज़ इण्डिया'' में बिहार को बौद्धिक विलक्षण से भरा हुआ बताया है।

यह सब जानने के बाद आज यकीन नहीं होता कि भारत के स्वर्णिम इतिहास का धनी यह राज्य वर्तमान में बीमार राज्यों की सूची में प्रथम स्थान रखता है। 94,164 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल व 10 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य आज मानव के विकास के तमाम सूचकांकों पर फ़िसड्डी नज़र आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज के आंकड़े बिहार के गौरवशाली इतिहास पर व्यंग्य कस रहे हों।

कमोबेश बिहार राज्य की यह हालत शिक्षा और युवाओं को लेकर है। चूँकि शिक्षा, युवाओं के भविष्य का आधार होती है। प्रस्तुत अध्ययन उक्त पृष्ठभूमि में बिहार राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान–2009 (रा.मा.शि.अ.) की राज्य के सभी जिलों के 22 लाख किशोरों की शिक्षा, उसकी गुणवत्ता, उपलब्धियों एवं खामियों को

* *पूर्व स्नातक छात्र* (सामाजिक विज्ञान विभाग), टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
** *पूर्व स्नातक छात्र* (सामाजिक विज्ञान विभाग), टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

Ch_1 to 3.indd 30 6/17/2015 10:46:04 AM

जानने की एक पड़ताल है, जिससे यह पता लग सकेगा कि गौरवशाली इतिहास के धनी इस राज्य में, आज इतना अंधियारा क्यों है...?

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान– परिचयात्मक दृष्टिकोण

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रूपी महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य राष्ट्र के किशोरों को उनकी पहुँच के स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस निमित्त सरकार ने हर पाँच किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल खोलने की परियोजना बनाई है। *सर्वशिक्षा अभियान* की सफ़लता के बाद माध्यमिक स्तर की शिक्षा के रिसावों को रोकने के लिए सरकार ने 2009 में रा.मा.शि.अ. की आधार शिला रखी। इसके दायरे में आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों के बालक-बालिकाएँ, ड्राप आउट बालक-बालिकाओं के साथ-साथ किसी भी प्रकार से 10वीं तक की शिक्षा से विलग बालक आते हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की दृष्टि

रा.मा.शि.अ. का लक्ष्य भारतवर्ष के किशोरों को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस दृष्टि से रा.मा.शि.अ. ने अग्रगामी कदम तय किए हैं-

1. किशोरों की शिक्षा तक पहुँच के लिए हर पाँच किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय खोलना। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यह दायरा 7 से 10 किलोमीटर तक का है।
2. 2017 तक नामांकन दर 100 गुणा करना।
3. 2020 तक सभी विद्यार्थियों का 100 गुना ठहराव बनाए रखना।
4. समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के किशोर, विशेषकर लड़कियों, ग्रामीण व सुदूर स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थी, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के किशोरों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों को माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूप से उपलब्ध करना।
5. विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना एवं विद्यालय संचालन की ज़िम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन को सौंपना।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं व्यय पोषण

रा.मा.शि.अ. 2009 के उद्देश्यों में राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से उसका नवोदित स्वरूप में गठन के साथ-साथ पहुँच, पाठ्यक्रम-विकास, ढाँचागत पहलू एवं समानता के साथ प्रासंगिक माध्यमिक शिक्षा को दिशा दी जाएगी। समान विद्यालयों की परिकल्पना को पोषित कर, प्रबंधन में ऐसे मूल्य स्थापित किए जाएँगे, जिनसे निजी विद्यालय भी इस महायज्ञ में साझेदारी कर सकेंगे। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय पोषण की योजना अग्रगामी स्वरूप में होगी-

1. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्व एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू करने में आने वाले कुल खर्च का 75: केंद्र व 25: राज्य सरकारों को वहन करना होगा।
2. उत्तरपूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का होगा।

रा.मा.शि.अ. के तहत राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तर पर, सार्वजनिक बैंकों में अलग-अलग खाते खोले जाएँगे। जिले स्तर पर खाताधारक जिला समन्वयक होंगे तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य एवं उपप्रधानाचार्य का संयुक्त खाता होगा।

4. 12वी पंचवर्षीय योजना में इस योजना का खर्च अनुपात केंद्र व राज्य के मध्य 75:25 के स्थान पर 50:50 हो जाएगा, लेकिन उत्तर पूर्व एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में यह अनुपात पूर्व की भाँति 90:10 का ही रहेगा।

पर दिख रहा है। रा.मा.शि.अ. के चलते विगत सत्र 2013-14 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3817 (UDISE 2013-14) हो गई है, साथ ही उससे लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2189448 (UDISE 2013-14) हो गयी है। आंकड़ों का यह इज़ाफ़ा बिहार में रा.मा.शि.अ. के महत्व को दर्शाता है।

बिहार राज्य में रा.मा.शि.अ. की क्रियान्विती की ज़िम्मेदारी राज्य की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की है, जिसका गठन राज्य में गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 9 अगस्त 2009

तालिका 1

आबंटित राशि			
वर्ष	*अनुमानित बजट*	*संशोधित बजट*	*दिया गया वास्तविक व्यय*
2009-10	1353.98	550.00	549.00
2010-11	1700.00	1500.00	1482.00
2011-12	2423.90	2512.85	2500.00
2012-13	3124.00	3172.00	3171.00
2013-14	3983.00	--	3045.88
कुल	12584.00	7734.85	10747.88

बिहार में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का परिचयात्मक दृष्टिकोण

63.82 (जनगणना 2011) फ़ीसदी साक्षरता दर के साथ बिहार साक्षरता के मामले में राष्ट्रीय साक्षरता औसत (74.08) से काफ़ी पीछे और बीमारू है। बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन के आलम को देखते हुए हम रा.मा.शि.अ. को वहाँ की माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से रामबाण औषधि के रूप में देख सकते हैं। इसका असर भी बिहार को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत् किया गया। यह परिषद् बिहार राज्य में इस दिशा की योजनाओं को लागू करने के लिहाज से नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद बिहार द्वारा इस योजना को ''जड़ स्तर तक की पहुँच अवधारणा" के रूप में लागू किया जा रहा है। इस कारण आज बिहार में विशेष फ़ोकस समूह के लड़के-लड़कियाँ, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि वर्गों के बच्चों

को नये परिप्रेक्ष्य में देखा और समझा जा रहा है, साथ ही रा.मा.शि.अ. के चलते बिहार में शैक्षिक शोधों व प्रशिक्षण से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष सुधार को दिशा भी मिली है। सार के तौर पर हम कह सकते हैं कि रा.मा.शि.अ. के योगदान व शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं एन.जी.ओ के अंशदान से बिहार में भी शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, सिर्फ़ ताल ठोकने की देर है...

बिहार में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ

बिहार के शैक्षिक संदर्भों का कतिपय कारणों से पिछड़ने के बाद रमसा जैसी महत्वाकांक्षी योजना ने इस दिशा के उन्नयन में कुछ पहल की, जिसके चलते आज बिहार में अग्रगामी शैक्षिक-प्राप्तियाँ प्राप्त हुई हैं–

1. रा.मा.शि.अ. के तत्वाधान में बिहार के शिक्षा विभाग में ''गोइंग टू स्कूल'' नामक गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से 9 जिलों, 835 विद्यालयों के 2205 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।
2. रा.मा.शि.अ. के तहत् प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय गठित करना प्रमुख प्रावधान है। जन घनत्व को देखते हुए बिहार सरकार ने इसी दायरे में माध्यमिक विद्यालयों के गठन का सुझाव दिया है।
3. वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में 344, 443 और 165 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमशः माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।
4. वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार सरकार के 318 विद्यालयों के स्तर उन्नयन के प्रस्ताव में केंद्र सरकार ने 201 विद्यालयों के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी है, इसके अलावा 1153 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति भी दी गई है।
5. वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक बिहार को रमसा के तहत 56143 लाख रु. आबंटित हुए, जिसमें से 12410 लाख रु. ही खर्च किये गये।
6. रा.मा.शि.अ. के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में जनवरी 2014 में विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, साथ ही हर जिले में 2 दिवसीय पुस्तक मेले भी लगाए गए।
7. वैश्वीकरण चुनौतियों का सामना करने के लिहाज से बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने रा.मा.शि.अ. के तहत् ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से राज्य के 636 शिक्षकों को अंग्रेज़ी भाषा विषय का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया।
8. शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत् शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 रखा गया है, साथ ही शिक्षकों की कुशलता-निर्माण पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।
9. रा.मा.शि.अ. के चलते नवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2009-10 में 869210 (SEMIS 2009-10) थी, जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 1165174 (UDISE-2013-14) हो गयी। इसी प्रकार कक्षा दसवीं में छात्रों की संख्या 746511 (SEMIS 2009-10) से बढ़कर 1024274 (UDISE-2013-14) हो गयी।

10. बिहार में सकल नामांकन दर की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है, परंतु रा.मा.शि.अ. के लागू होने के बाद उसमें 14.45 फीसदी का सुधार दर्ज किया गया। वर्ष 2013–14 में सकल नामांकन दर 49.45 फीसदी है, जिसे 2017 तक 65 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
11. वर्ष 2013–14 में केंद्रीय योजना के अंतर्गत सूबे के शैक्षणिक उपखंडों में 530 आदर्श विद्यालय खोलने की योजना है।
12. रा.मा.शि.अ. के लागू होने पर जेंडर विषमता सूचकांक में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। जेंडर विषमता सूचकांक 2009–10 में 0.83 था, जो 2013 में बढ़कर 1.02 हो गया है। यह आंकड़े रा.मा.शि.अ. के चलते जेंडर भेद को कम होता दर्शा रहे हैं, जिसे अग्र तालिका व रेखाचित्र से स्पष्ट किया जा रहा है–

जेंडर पैरिटी इंडैक्स (Gender parity index): ix-x

तालिका–2

जिले	*2009.10*	*2013.14*
पश्चिमी चंपारन	0.77	1.01
पश्चिमी चंपारन	0.78	1.12
शिवहर	0.92	1.11
सीतामढ़ी	0.89	1.05
मधुबनी	0.71	1.01
सुपौल	0.53	0.89
अररिया	0.64	0.94
किशनगंज	0.71	1.19
पूर्णिया	0.75	1.03
कटिहार	0.76	0.88
मधेपुरा	0.6	0.89
सहरसा	0.55	0.80
दरभंगा	0.72	0.94
मुज़फ्फरपुर	0.97	1.09
गोपालगंज	0.92	1.13
सिवान	0.82	1.13
सारन	0.89	1.01
वैशाली	1.03	1.14
समस्तीपुर	0.93	1.05
बेगुसराय	0.99	1.11
खगरिया	0.83	0.98
भागलपुर	0.89	1.03
बंका	0.78	0.95
मुंगेर	0.92	0.92
लखीसराय	0.79	0.79
शेखपुरा	0.79	1.01
नालंदा	0.8	0.92
पटना	0.94	1.21
भोजपुर	0.76	1.02
बक्सर	0.79	1.08
कैमुर	0.9	0.99
रोहतास	0.82	1.08
जेहानाबाद	0.75	0.87
औरंगाबाद	0.84	0.98
गया	0.84	1.07
नवादा	0.71	1.00
जमुई	0.64	0.80

अरवल	0.68	0.85
बिहार	0.83	1.02

स्रोत– UDISE 2013-14 SEMIS 2011-12

बिहार में रा.मा.शि.अ. के माध्यम से जो माध्यमिक शिक्षा के विकास की अलख जगी है, तो वहीं दूसरी ओर इस दिशा में कुछ रिसाव व बाधाएँ भी प्रचलन में हैं, जो राज्य में इस दिशा की चुनौती

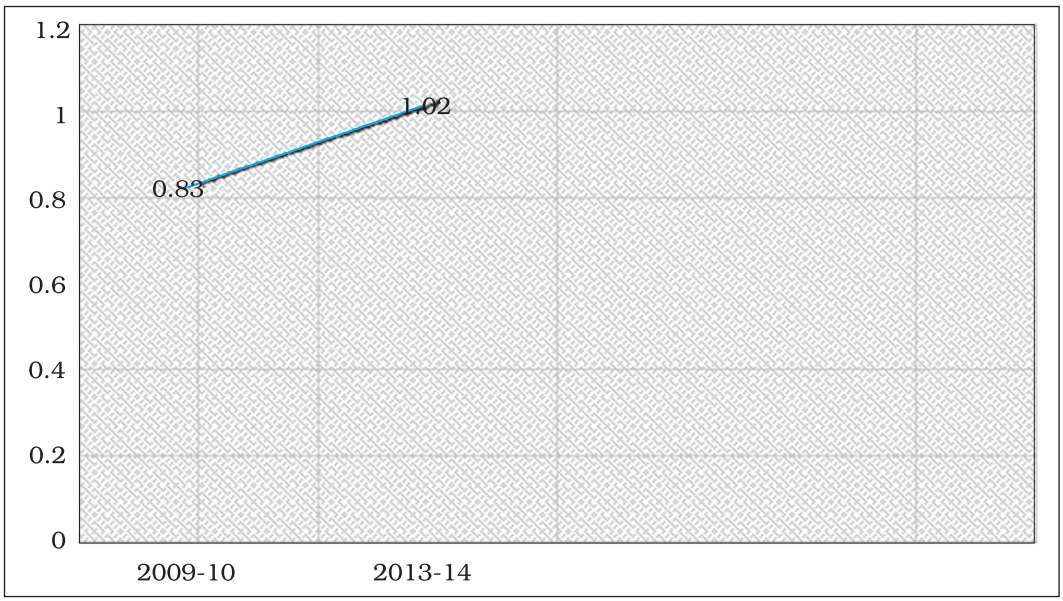

स्रोत– UDISE 2013-14 SEMIS 2011-12

13. रा.मा.शि.अ. के माध्यम से राज्य में आदर्श विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है।
14. रा.मा.शि.अ. के माध्यम से किशोरों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सुदृढ़ ढाँचा बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ – बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में

हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

1. वर्ष दो हज़ार 11–12 में केंद्र सरकार ने 165 विद्यालयों के उन्नयन की स्वीकृति दी थी, परंतु इसे लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने कोई ठोस व मज़बूत कदम नहीं उठाए। इसी क्रम में सत्र 2013–14 में भी 201 विद्यालयों के उन्नयन कार्य भी लटका हुआ है, जो इस दिशा की लापरवाही को दर्शाता है।
2. वर्ष 2011–12 में एम.एच.आर.डी. भारत सरकार ने राज्य को विद्यालय निर्माण के लिए 9822.28 लाख रु. आबंटित किये गये,

जिसका 31.12.2013 तक किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक 56143.92 लाख रु. आबंटित हुए, जिसमें से मात्र 12410 रु. ही इस्तेमाल हो पाए।
4. बिहार राज्य का 17.06 हिस्सा नक्सल प्रभावित है, उस क्षेत्र में भवन निर्माण के कार्य में नक्सली बाधाएँ डाल रहे हैं।
5. बिहार राज्य की भौगोलिक सूचना प्रणाली का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, इस कारण 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय खोलने में कठिनाई हो रही है, जिसका खामियाज़ा दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
6. लाख प्रयासों के बावजूद बिहार में शिक्षा अधिकार विधेयक के मानक 1:30 के शिक्षक-छात्र के अनुपात को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वर्तमान में यह अनुपात 1:85 है, जिसे 2016 तक 1:40 तक करने के प्रयास जारी हैं।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी – बिहार राज्य की समृद्ध विरासत और वर्तमान की शैक्षिक दशाओं की स्थिति में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। तमाम आंकड़े वहाँ के शैक्षिक पिछड़ेपन की स्पष्ट कहानी कह रहे हैं, ऐसे में ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' से राज्य में माध्यमिक शिक्षा की दिशा में सुधारवादी दृष्टिकोणों का आगाज़ हुआ है। रा.मा.शि.अ. के बिहार में लागू होने के बाद माध्यमिक शिक्षा की आधारभूत संरचना, नामांकन, शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षक-छात्र अनुपात एवं जेंडर विषमताओं की दृष्टि से काफ़ी विकास हुआ है, यद्यपि पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति अभी दूर है, लेकिन इस प्रकार के प्रयास अनवरत् जारी रहे, तो बिहार में उत्कर्ष व गुणवत्तापरक स्कूली शिक्षा का लक्ष्य अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकेगा। इस दृष्टि से बिहार राज्य में रा.मा.शि.अ एक महत्वपूर्ण व आवश्यकता पर आधारित उपागम है।

बिहार राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सफ़ल क्रियान्वयन हेतु सुझावात्मक विवेचना

बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, लालफ़ीताशाही, जागरुकता का अभाव, सार्वजनिक कार्यों की उपेक्षा आदि प्रमुख कारक हैं यदि कड़ी निगरानी, सतत् मॉनीटरिंग एवं जवाबदेयता के स्तर को बढ़ाया जाए, तो इस दिशा में भी काफ़ी सुधार की आशा की जा सकती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बिहार में रा.मा.शि.अ एक आवश्यक कदम है, जिसके सफ़ल क्रियान्वयन की दृष्टि से अग्रकदम उठाए जाएँ, तो राज्य के शैक्षिक विकास की दृष्टि से बेहतर होगा-

1. रा.मा.शि.अ की योजनाओं के माध्यम से बिहार के शिक्षकों की दक्षता निर्माण व उनके पेशेवर विकास पर अधिकाधिक निवेश करना चाहिए।
2. मौजूदा शिक्षा-व्यवस्था को नवाचारी कदमों के साथ पुनः गढ़कर इस दिशा की नयी परिकल्पनाओं को जन्म दिया जाए, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा में नयी रणनीतियों व अनुभूतियों को प्रोत्साहित किया जा सके।
3. फिनलैण्ड की भांति बिहार राज्य के शिक्षक 4 घंटे अध्ययन करवाएँ तथा 2 घंटे अपनी

पेशेवर दक्षताओं को बढ़ाने में लगाएँ, तो अच्छा रहेगा।

4. शैक्षिक बजट का स्तर व उनके आबंटन में सुधार की आवश्यकता है। इस दिशा में बजट की मात्रा, जो वर्तमान में जी.डी.पी. का 3.1 है, को और बढ़ाया जाए तथा समय पर उसका आबंटन हो।
5. बजट की वित्तीय वैधानिकता का समय वर्तमान में 1 वर्ष का है, जो कम है, इसे परिस्थितियों को देखते हुए खर्च करने के लिहाज़ से और बढ़ाया जाए तो लाभदायक होगा।
6. मॉस परियोजनाओं के आयोजन व क्रियान्वयन में राज्य की अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों की आवश्यकता में विविधता व भिन्नता पाई जाती है।

उपर्युक्त सुझावों के समावेशन से रा.मा.शि.अ जैसी महत्वकांक्षी योजना बिहार ही क्या, सभी राज्यों के लिए फलदायी प्रक्रम साबित होगी।

संदर्भ

mhrd.gov.in/rashtriya_madhyamik_shiksha_abhiyan
www.bmsprmsa.in/rmsa.htm
planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/pdf/12fyp_vol3.pdf